



अधिकतम : 26° C
न्यूनतम : 16° C

अबरे सुपाता नही, छापता है

शाह टाइम्स

मेरठ, मंगलवार 7 अप्रैल 2026 मेरठ संस्करण: वर्ष 19 अंक 305 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00



विस्तृत खबरों के लिए QR कोड स्कैन करें।
मुफ्त पढ़ें E-paper

shahtimes2015@gmail.com

वैसाख कृष्ण पक्ष 5 विक्रमी सम्वत् 2083

18 शबाल 1447 हिजरी

नई दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, हल्द्वारी, मुतादाबाद, बरेली, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित



सत्ता नहीं, संस्कार की है भाजपा की विकास यात्रा: योगी



ऑरेंज कैप की दौड़ में समीर रिजवी सबसे आगे खेल टाइम्स



राजनीति का नया भूगोल लोकसभा विस्तार व नारी शक्ति का नया उदय सम्पादकीय



युद्ध कई साल चला, तो भी नहीं होगी मिसाइलों की कमी: ईरान

ईरान ने दुकराया युद्धविराम का प्रस्ताव, हमले जारी रहने तक नहीं होगी सीधी बातचीत

तेहरान, वार्ता

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ अमेरिका की ओर से सैन्य कार्रवाई की चेतावनियां मिल रही हैं, तो दूसरी ओर ईरान खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बना रहा है।

इस बीच, ईरान ने सोमवार को कहा कि उसने मध्यस्थों की ओर से पेश किए गए प्रस्तावों पर अपना जवाब तैयार कर लिया है। हालांकि, उसने यह भी कहा कि जब तक अमेरिका व इजरायल हमले तेज करते रहेंगे, वह सीधी वार्ता में शामिल नहीं होगा।



शामिल नहीं होगा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका का 15 सूत्रीय प्रस्ताव अत्यधिक मांगों वाला है। हमने अपनी मांगों का एक

अस्थायी युद्धविराम के बदले होर्मुज स्ट्रेट खोलने से किया इन्कार

ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर इजरायल का हमला

तेल अवीव/तेहरान। इजरायल ने सोमवार को ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर फिर से मिसाइल हमला किया। यह दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है, जो ईरान और कतर के बीच फैली हुई है। इससे पहले इजरायल ने 18 मार्च को भी इस गैस फील्ड पर हमला किया था। तब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा

ट्रम्प ने यहां अटैक करने से मना किया था, जॉर्डन के अमेरिकी सैन्य ठिकाने के पास धमका

था कि उन्हें इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी। तब ट्रम्प ने ये भी कहा था कि इस तरह के और हमले नहीं

होने चाहिए। वहीं सोमवार को जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने के पास भी धमकाओं की आवाज सुनी गई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह हमला अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका और इजरायल के हमले बढ़ें, तो वह ग्लोबल सप्लाय चैन को ठप कर देगा।

हमले में IRGC के खुफिया एजेंसी के प्रमुख की मौत

तेहरान। आईआरजीसी के खुफिया संगठन के प्रमुख मेजर जनरल मजीद खार्दमी की अमेरिका-इजरायल के हमले में मौत हो गई है। आईआरजीसी ने सोमवार को एक बयान में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि आईआरजीसी के खुफिया संगठन के प्रमुख मजीद खार्दमी की सोमवार सुबह अमेरिकी-इजरायली हमले में मौत हो गई।

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली विस की सुरक्षा में चूक, बैरियर तोड़कर घुसी कार

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा कैम्पस में सोमवार दोपहर को सुरक्षा में चूक हुई। दोपहर करीब 2 बजे यूपी नंबर की कार वीआईपी एंटी वाला गेट नंबर-2 की बैरिकाडिंग तोड़कर अंदर घुसी। कार ड्राइवर ने नकाब पहना हुआ था। अधिकारियों के मुताबिक ड्राइवर सीधे विधानसभा स्पीकर विजेन्द्र गुप्ता के कार्यालय की ओर गया और पार्च के पास गुलदस्ता रखकर कार समेत मौके से फरार हो गया। हालांकि बम जैसी कोई चीज नहीं मिली। घटना के बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची है। गेट नंबर 2 पर अब सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने आरोपी समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में से एक उत्तर प्रदेश के पौलीभौत का रहने वाला सरबजीत है।

दो जहाज जल्द 60 हजार टन एलपीजी लेकर पहुंचेंगे भारत

नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बावजूद भारत के लिए राहत की खबर है। सरकार ने बताया कि एलपीजी (रसाई गैस) लेकर आ रहे भारत के दो जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं और जल्द भारत पहुंचेंगे। इन जहाजों के नाम ग्रीन सान्वी और ग्रीन आशा हैं। इनमें कुल मिलाकर 60 हजार टन से ज्यादा गैस है। ग्रीन सान्वी 7 अप्रैल और ग्रीन आशा 9 अप्रैल तक भारत पहुंच सकते हैं। सरकार के मुताबिक, दोनों जहाज पूरी तरह सुरक्षित हैं और इनमें भारतीय नाविक भी सवार हैं। एक जहाज में करीब 46 हजार टन और दूसरे में लगभग 15 हजार टन गैस है।

ब्रह्मोस प्रोजेक्ट से जुड़े अलेक्जेंडर लियोनोव की मौत

प्रास्को। ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट से जुड़े रूस के प्रमुख वैज्ञानिक अलेक्जेंडर लियोनोव का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे रूस के प्रमुख मिसाइल डिजाइनरों में शामिल थे। लियोनोव एनपीओ मोशिनोस्ट्रॉएनिया के सीईओ और चीफ डिजाइनर थे, जो भारत-रूस की ब्रह्मोस एग्जोस्पेस का प्रमुख साझेदार है। उन्हें उन्नत मिसाइल तकनीक के विकास के लिए जाना जाता था। उन्होंने जिरकान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल समेत कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया। उन्होंने प्रिंट, वल्कन और बार्सिटन जैसे मिसाइल और कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स के विकास में भी भूमिका निभाई थी।

बंगाल SIR: सुप्रीम कोर्ट गंभीर

मतदाता सूची अपडेट करने के लिए तय की एक दिन की समयसीमा

टिब्यूनल को भी निर्देश जारी किए

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची अपडेट के लिए एक दिन की समयसीमा तय की है। शीर्ष कोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) न्यायाधिकरणों को दस्तावेजों को फिर से देखने का आदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमने न्यायाधिकरणों से अनुरोध किया है कि वे पूरी दस्तावेजी प्रक्रिया को फिर से देखें, जिसमें न्यायिक अधिकारियों की ओर से दिए गए कारण भी शामिल हैं, ताकि किसी भी तरह के संदेह को दूर किया जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने उनसे अनुरोध किया है कि पक्षों की निष्पक्ष सुनवाई की जाए। निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम

मालदा घटना: हाईकोर्ट सीजे का फोन न उठाने पर मुख्य सचिव को लगाई फटकार, कहा- माफी मांगो

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों के घेराव की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को मालदा के मामले से जुड़े दस्तावेज एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया और कहा कि स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार अर्चुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए मालदा की घटना से जुड़े सभी मामलों की जांच एनआईए को सौंप दी है।

राजमार्ग पर आवारा पशु सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार और अन्य को सुप्रीम नोटिस जारी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आवारा पशुओं को नियंत्रित करने की एक याचिका पर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए हैं। न्यायालय ने देश के राजमार्गों पर आवारा पशुओं के प्रबंधन से जुड़े विषयों में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर जवाब मांगा है। 'लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल' द्वारा दायर इस याचिका में राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर विशेष रूप से दुर्घटना-संबंधित हिस्सों पर अनिवार्य रूप से बाड़ लगाने की मांग की गई थी।

उग्र में RO व ARO परीक्षा का परिणाम घोषित, 419 सफल

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने स्टीमशिप अधिकारी (आरओ) एवं सहायक स्टीमशिप अधिकारी (एआरओ) परीक्षा-2023 का परिणाम रविवार देर रात घोषित कर दिया। आयोग के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि परीक्षा में कुल 419 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जिनमें 338 स्टीमशिप अधिकारी तथा 81 सहायक स्टीमशिप अधिकारी शामिल हैं। परिणाम के अनुसार अनिल पांडेय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि आदित्य प्रताप सिंह दूसरे तथा लक्ष्मी वर्मा तीसरे स्थान पर रहें।

बागपत में तोतों के तीन तस्कर अरेस्ट

शाह टाइम्स संवाददाता

बागपत। पुलिस और एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन की टीम ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास से 170 दुर्लभ प्रजाति के तोते बरामद किए हैं। इस मामले में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके दो साथी मौके से फरार हो गए। यह कार्रवाई मवीकला टोल के निकट एक संदिग्ध गाड़ी को रोकने के बाद की गई। गाड़ी की तलाशी के दौरान उसमें सात प्लास्टिक के बक्से मिले, जिनमें तोतों का तस्करों के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस और एनिमल



वेलफेयर एसोसिएशन की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है। एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने बताया कि उन्हें तोतों की तस्करों के संबंध में सूचना मिली थी। इसके बाद एक जाल बिछाया गया और बागपत पुलिस से संपर्क किया गया। गिरफ्तार किए गए तस्करों की पहचान कन्नौज निवासी खुर्शीद, मोहसिन और राजा के रूप में हुई है। फरार हुए दो साथियों के नाम शमीम और

सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा लाया गया महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। 190 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर वाले इस प्रस्ताव को 6 अप्रैल 2026 को राज्यसभा के सभापति द्वारा खारिज किया गया। विपक्ष ने उन पर मतदाता सूची में हेरफेर और पक्षपातपूर्ण व्यवहार के आरोप लगाए थे।

टीएमसी के नेतृत्व में विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस दिया था, लेकिन यह बट सत्र में आगे नहीं बढ़ पाया। विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार पर मतदाता सूची से नाम हटाने, चुनावी प्रक्रिया में पक्षपात और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। सीईसी को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान महाभियोग की कठिन प्रक्रिया (विशेष बहुमत) की आवश्यकता होती है, जो भारत में अब तक किसी सीईसी के



190 से अधिक सांसदों ने किए थे हस्ताक्षर

इतिहास में पहली बार आया था सीईसी को हटाने का प्रस्ताव

खिलाफ नहीं हुई। यह भारत के संसदीय इतिहास में किसी सेवारत मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की पहली कोशिश थी। सुओं के मुताबिक इस पहल की शुरुआत टीएमसी ने की थी। पार्टी ने अन्य विपक्षी दलों को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए सहमत किया। इससे पहले

मुजफ्फरनगर में तीन को फांसी की सजा सुनाई

शाह टाइम्स ब्यूरो

मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर के सनसनीखेज कांड अधिवक्ता समीर सैफी अपहरण हत्या और लाश को छुपाने के मामले में अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि इस कांड के सहयोगी नौकर को सात वर्ष की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इसमें दस लाख रुपये का आर्थिक दण्ड भी लगाया है। इस फैसले के बाद पीडित परिवार ने कोर्ट का शुक्रिया ही नहीं किया, राहत की सांस भी ली है।

बता दें कि 15 अक्टूबर 2019 को अधिवक्ता समीर सैफी अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे। काफी समय बाद भी जब समीर सैफी घर नहीं लौटे, तो परिवार को चिंता ने उन्हें थाने तक पहुंचा दिया था। अधिवक्ता के संबंध में नगर कोतवाली पुलिस को जानकारी दी गई, जहां परिवार के लोग पुलिस समीर सैफी की तलाश में जुट गए थे। 19 अक्टूबर को अधिवक्ता समीर सैफी का शव भोपा थाना क्षेत्र के गांव सीकरी के जंगल में दबा हुआ मिला था। अधिवक्ता का शव मिलने के बाद यह मामला पूरी तरह सनसनीखेज बन गया था और इस मामले की छानबीन के दौरान पुलिस ने पाया

भाजपा के स्थापना दिवस पर राष्ट्र प्रथम का संकल्प

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। भाजपा के 47वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ-साथ कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दीं और 'राष्ट्र प्रथम' के संकल्प को दोहराया। श्री नवीन ने इस मौके पर भाजपा मुख्यालय पर कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए 'राष्ट्र सर्वोपरि' के संकल्प को दोहराया और 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनसंघ से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी



राजनीतिक पार्टी बनने तक का यह सफर कार्यकर्ताओं के त्याग और समर्पण का परिणाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो और असम में एक चुनावी रैली के माध्यम से कार्यकर्ताओं को बधाई दी और राष्ट्र प्रथम का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा 'राष्ट्र प्रथम'



के सिद्धांत पर चलते हुए समाज सेवा में अग्रणी रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को निरवस्था सेवा, समर्पण और सुरासन के प्रति प्रतिबद्धता को सराहना करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों ने पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। उन्होंने उन अनगिनत कार्यकर्ताओं को भी याद किया,

'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होने की जरूरत: पीएम मोदी

जिनके त्याग और बलिदान ने पार्टी के विकास को आकार दिया। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी के रूप में खड़ी है, जो लोगों की भावनाओं को अपने दृष्टिकोण के केंद्र में रखती है। यह केंद्र और विभिन्न राज्यों में हमारे काम में भी झलकता है। भाजपा एक 'विकसित भारत' बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारा सामूहिक संकल्प इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता रहे और भारत को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पीडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से प्रेरित भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र पुनर्निर्माण का संकल्प है।

बातचीत, जंग साथ-साथ

पश्चिमी एशिया में जारी ईरान-अमेरिका/इस्राइल युद्ध धमके का नाम नहीं ले रहा है। 137 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इस युद्ध का कहीं से भी अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि इस बीच एक अच्छी खबर भी आई है जिसमें पद के पीछे इस संघर्ष को रोकने के लिए कोशिशों की बात सामने आई है। पहली बार ईरान ने माना है कि उसे मध्यस्थता के जरिये से अमेरिका की तरफ से युद्ध को रोकने के लिए प्रस्ताव मिला है। हालांकि ईरानी विदेश मंत्रालय ने ऐसा कहते हुए यह भी जोड़ा कि जब तक अमेरिका व इस्राइल हमले तेज करते रहेंगे, वह सीधे वार्ता में शामिल नहीं होगा। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका का 15 सूत्रीय प्रस्ताव अत्यधिक मांगों वाला है। मंत्रालय का यह भी कहना है कि ईरान ने भी अपनी मांगों का एक अलग सेंट तैयार कर लिया है और उसे औपचारिक रूप दे दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने तेहरान में कहा कि इस्राइल अमेरिका की कोई रेडलाइन नहीं है और वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कोई परवाह नहीं करते। उन्होंने अमेरिका के कथित 15 सूत्रीय प्रस्ताव को तर्कहीन करार दिया। उनका कहना था कि किसी भी समझौते को तभी स्वीकार किया जाएगा जब ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में होगा। उन्होंने अस्थायी युद्ध के बदले होमरुज को खोलने के लिए मना कर दिया। एक अन्य सीनियर ईरानी अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रस्ताव की समीक्षा चल रही है लेकिन दबाव में फंसला नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान अभी भी मध्यस्थता की भूमिका में बना हुआ है। ईरान ने साफ किया कि युद्ध विराम के बलदे होमरुज नहीं खोलेगा। ईरान का अभी भी यह मानना है कि अमेरिका स्थायी युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है और ईरान के लिए अस्थायी युद्ध का कोई मतलब नहीं है। बात घूम-फिरकर फिर वहीं आ जाती है, जब तक दोनों पक्षों के बीच में ऐसे कदम नहीं उठाए जाएंगे, जिससे जो अविश्वास की खाई जो बहुत गहरी हो चुकी है, उसको पाटा नहीं जाएगा तब तक किसी शांति समझौते पर पहुंचना आसान नहीं होगा। इस समय की यही दिखाने दे रहा है। शांति के प्रयास भी हो रहे हैं और युद्ध की तीव्रता में किसी तरह की कोई कमी आती दिखाई नहीं दे रही है। दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इन हमलों का दायरा इतना बढ़ चुका है कि अब इसकी जद में पुल, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हेल्थ सेंटर भी आने लगे हैं। सवाल है ऐसे में संघर्ष विराम पर कैसे अमल होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह सुपर पावर के राष्ट्रपति को बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। वह अभी भी ईरान को धमकी भरी भाषा में चेता रहे हैं। उन्होंने अपने दस दिनों के अल्टीमेटम में अब 48 घंटों का अतिरिक्त इजाजा कर दिया है, लेकिन वह भी धमकी के साथ कि होमरुज को खोलो नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा।

नतीजा शहर छोड़ो, गांव भागो

प्रधानमंत्री मोदी के पास रसोई गैस (एलपीजी) संकट से निपटने की कोई नीति नहीं है और इस समय भी वही अवस्था देखने को मिल रही है जो देश के लोगों ने कोविड के समय देखी थी, मोदी जी ने कहा था कि एलपीजी संकट को कोविड की तरह हैंडल करेंगे और सच में वही किया, बिल्कुल कोविड के जैसे ही नीति शून्य, घोषणा बड़ी और बोझ गरीबों पर, हर रोज 500-800 की दिहाड़ी कमाने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रसोई गैस पहुंच से बाहर हो गई है, रात को घर लौटते मजदूर के पास चूल्हे जलाने तक के पैसे नहीं, नतीजा शहर छोड़ो, गांव भागो, जो मजदूर कपड़ा मिल और फैक्ट्रियों की रीढ़ हैं, आज वही टूट रहे हैं। कपड़ा क्षेत्र पहले से ही गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में है।

-राहुल गांधी, नेता विपक्ष, लोकसभा

भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में 16 अप्रैल का दिन एक युगांतरकारी मोड़ साबित हो सकता है। केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को धरातल पर उतारने के लिए एक साहसिक और दूरगामी योजना तैयार की है। इस योजना के केंद्र में केवल महिला आरक्षण ही नहीं, बल्कि लोकसभा की संरचना में अब तक का सबसे बड़ा विस्तार भी शामिल है। मसलन नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बड़े संशोधनों के साथ ही लोकसभा की 50 प्रतिशत सीटों की बढ़ोतरी की तैयारी कर ली है। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य न केवल विधायी निकायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है, बल्कि दशकों से लंबित परिसीमन की प्रक्रिया को एक नई दिशा देना भी है। सरकार द्वारा इस तैयारी के लिए खींचे गए खाकें को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि वह महिलाओं को संसद में भेजने के अपने वादे को 2029 के आम चुनाव तक हर हाल में पूरा करना चाहती है। देश को उम्मीद है कि लोकसभा की नई संरचना न केवल भारत की बढ़ती आबादी का प्रतिनिधित्व करेगी, बल्कि नारी शक्ति को राष्ट्र के नीति-निर्माण में बराबर का हिस्सेदार बनाएगी।

संसद के बजट सत्र के अंतिम दिन केंद्र सरकार ने भारतीय राजनीति और संसदीय इतिहास में उस समय चौकाने वाला निर्णय लिया, जिसमें अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने वाले बजट सत्र को समाप्त करने के बजाय, 16 अप्रैल सुबह 11 बजे तक के लिए टाल दिया गया है। यानी संसद का बजट सत्र का यह विशेष हिस्सा अब 16 से 18 अप्रैल तक फिर से चलेगा। केंद्र सरकार का मकसद महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को समय से पहले जमीन पर उतारना है। सरकार का पूरा फोकस अब उस कानूनी अडचन को खत्म करना है, जो महिला आरक्षण और जनगणना तथा परिसीमन के बीच फंसी हुई है। दरअसल 2023 में पास हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुताबिक, आरक्षण अगली जनगणना के बाद ही लागू हो सकता था, जिसमें वर्षों का समय लगना स्वाभाविक था। अब सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर ही लंबित परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संशोधन बिल लाने की तैयारी में है। सरकार चाहती है कि महिलाओं को उनके हक के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। इसलिए जनगणना और परिसीमन की तकनीकी अडचनों को दूर करने के लिए पथ संभलाने का पथ साबित होगा।

इस सत्र के विस्तार का सबसे बड़ा आकर्षण लोकसभा सीटों का पुनर्गठन हो सकता है। चर्चा है

राजनीति का नया भूगोल लोकसभा विस्तार व नारी शक्ति का नया उदय



कि सरकार सदन में सीटों की संख्या 543 में 50 फीसदी सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे लोकसभा की 816 सीटें होने पर 33 प्रतिशत यानी एक-तिहाई आरक्षण के फार्मूले के तहत लोकसभा में लगभग 273 सीटें सीधे महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। मसलन इन 273 सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उनके आरक्षित कोटे के भीतर सीटें तय होंगी।

संसद में यदि यह संशोधन पास होता है, तो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही देश की संसद का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा और महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच जाएगी। माना जा रहा है कि इसके लिए बजट सत्र की आगामी तीन दिन की बैठकों में सरकार जहां एक संविधान संशोधन विधेयक के जरिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव करेगी। वहीं दूसरा सामान्य विधेयक परिसीमन अधिनियम में संशोधन लाएगी।

इन दोनों प्रस्तावित कानून 31 मार्च 2029 से लागू किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो आगामी लोकसभा चुनावों और ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में महिलाओं को आरक्षण मिल सकेगा। यही फार्मूला राज्यों की विधानसभाओं में भी लागू किया जाएगा, ताकि

पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का एक समान ढांचा तैयार हो सके। माना जा रहा है कि उत्तर बंगाल दक्षिणसीटों की संख्या बढ़ने से बड़े राज्यों, विशेषकर हिंदी भाषी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में भारी उछाल आएगा। नए परिसीमन के जरिए राज्यों में फिलहाल संसदीय सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी होगी और उत्तर प्रदेश में यह संख्या सबसे ज्यादा होकर तीन अंक में पहुंच जाएगी।

लोकसभा का ऐतिहासिक विस्तार

वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, जो 1971 की जनगणना के आधार पर टिकी हुई है। सरकार के नए प्रस्ताव के अनुसार यदि सीटों में 50 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो यह संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी। इस विस्तार का आधार 2011 की जनगणना को बनाया जाएगा यानी अब 2011 के आंकड़ों के आधार पर ही सीटों का पुनर्गठन (परिसीमन) किया जाएगा। यह कदम इसलि महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जनगणना में होने वाली देरी के कारण आरक्षण के क्रियान्वयन में बाधा आ रही थी। यदि ए दोनों विधेयक संसद में पारित होते हैं, तो महिला आरक्षण के बाद यूपी में सबसे ज्यादा 40 लोकसभा सीटें बढ़ेंगी। 80 से बढ़कर 120 हो जाएंगी। महाराष्ट्र में 48 से बढ़कर 72 हो जाएंगी। जिनमें महिलाओं के लिए 24 सीटें

ओ.पी. पाल



आरक्षित होगी। बिहार में महिला सीटों की संख्या 20 हो सकती है, जहां कुल सीटें 40 से 60 तक पहुंच सकती है। मध्यप्रदेश में 29 से 44 सीटों में 15 महिला आरक्षित सीटें बढ़ सकती हैं। तमिलनाडु में 39 से 59 प्रस्तावित सीटों में 20 और दिल्ली प्रस्तावित 11 में 4 यानी महिला सीटें होंगी। झारखंड में 7 महिला आरक्षित सीटें बढ़ने का अनुमान है, जहां फिलहाल 14 सीटें हैं। ऐसे ही अन्य राज्यों की सीटें भी नए परिसीमन में बढ़ेंगी।

कानूनी और राजनीतिक चुनौतियां

सरकार को हालांकि इस ऐतिहासिक बदलाव को अमली जामा पहनाने के लिए ए दो मोर्चों पर काम करना होगा। इसके लिए संविधान संशोधन के लिए सरकार को संसद के दोनों सदन में विशेष बहुमत की आवश्यकता है।

यानी इन दोनों विधेयकों को पास कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होगा। इसी वजह से सरकार विपक्ष का समर्थन जुटाने में लगी है। यही कारण है कि इसके लिए गुमहमूरी अमित शाह सपा, राजद, बीजद, वार्डएसआर कांग्रेस, एनसीपी (एनपी) और एआईएमआईएम जैसे विपक्षी दलों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं। दरअसल विपक्ष में खासतौर से कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दल लगातार मांग कर रहे हैं कि महिला कोटे के भीतर ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान शामिल नहीं है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार सरकार इसी फार्मूले पर राज्यों की विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ाने और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की योजना है, ताकि पूरे देश में एक जैसा ढांचा रहे।

इतिहास बदलने और भविष्य गढ़ने वाले कदम

वारिसों और महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकार अब सुनिश्चित और संरक्षित हैं। यह प्रावधान माननीय और दुरुपयोग को रोकता है और दानकर्ताओं के विश्वास को सुदृढ़ करता है। संघर्षों की संख्या बढ़ेगी और उनका उपयोग स्पष्ट, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित होगा। यह कदम वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को समाप्त करने में मदद करेगा और सुरक्षा की नई भावना पैदा करेगा। विवाद समाधान प्रक्रिया में सुधार न्याय की गति को तेज करेगा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। अब ट्रिब्यूनल के फैसलों पर हाईकोर्ट में अपील का अधिकार होगा।



प्रो. आर.के. जैन

जब कोई कानून केवल कागज़ों तक सीमित नहीं रहकर समाज की रोजमर्रा की जिंदगी में वास्तविक बदलाव लाता है, तभी उसका ऐतिहासिक महत्व अमिट हो जाता है। राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी के साथ वक्फ संशोधन कानून ने भारतीय वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में एक नए युग की शुरुआत कर दी है। यह केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक न्याय की दिशा में एक निर्णायक और क्रांतिकारी कदम है। पुराने तंत्र में भ्रष्टाचार, मनमानी और अतिक्रमण ने संपत्तियों से मिलने वाले वास्तविक लाभ को लगातार रोके रखा था। अब वक्फ बोर्डों का अधिकार, उत्तरदाई प्रबंधन और समावेशी, पिटकोण के साथ काम करेगा। इसका असर केवल संपत्तियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गरीबी उन्मूलन जैसे मूलभूत जरूरतों में सीधे दिखाई देगा। यह परिवर्तन करोड़ों मुस्लिम परिवारों के लिए सुरक्षा, विश्वास और समृद्धि का एक नया संदेश लेकर

आया है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पहले अनियमितताओं और विवादों की लंबी श्रंखला रही, जिसने उनकी वास्तविक उपयोगिता और विकास को लगातार बाधित किया। मनमाने दावे, लंबित मुकदमें और अतिक्रमण ने कई संपत्तियों को विवादास्पद और अनुपयोगी बना दिया था। अब डिजिटल पोर्टल और ऑटोमेशन के माध्यम से प्रत्येक संपत्ति का पूरा जीवनचक्र ट्रैक किया जाएगा। पंजीकरण, लेखा-जोखा, ऑडिट और मुकदमेबाजी सभी ऑनलाइन और पारदर्शी होंगे। छह माह के भीतर सभी संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज हो जाएंगी, जिससे कोई भी संपत्ति छिपी नहीं रहेगी। यह पारदर्शिता भ्रष्टाचार को कम करेगी और वक्फ बोर्डों को एक वैज्ञानिक, उत्तरदाई और आधुनिक संस्था में परिवर्तित कर देगी। परिणामस्वरूप, संपत्तियों का उपयोग अधिक प्रभावी, सुव्यवस्थित और न्यायसंगत ढंग से सुनिश्चित होगा।

जिला कलेक्टर को संपत्ति सर्वेक्षण और विवाद समाधान की जिम्मेदारी दी गई है, जो प्रबंधन का सबसे मजबूत स्तंभ साबित होगा। अब निर्णय केवल सरकारी रिपोर्टों और निष्पक्ष जांच पर आधारित होंगे। अतिक्रमण स्वतः रोक जाएगा और संपत्तियां उनके वास्तविक लाभार्थियों तक सुरक्षित रूप से पहुंचेंगी। कलेक्टर का समयबद्ध और तथ्यपरक ट्रिब्यूनल हर निर्णय को मजबूत और भरोसेमंद बनाएगा। इसके परिणामस्वरूप, वक्फ संपत्तियां शीघ्र और प्रभावी कल्याण कार्यों में लागू होंगी। विवाद कम होंगे, संपत्तियों का विकास तेजी से होगा और गरीब, विधवा एवं वंचित वर्गों तक लाभ

आया है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पहले अनियमितताओं और विवादों की लंबी श्रंखला रही, जिसने उनकी वास्तविक उपयोगिता और विकास को लगातार बाधित किया। मनमाने दावे, लंबित मुकदमें और अतिक्रमण ने कई संपत्तियों को विवादास्पद और अनुपयोगी बना दिया था। अब डिजिटल पोर्टल और ऑटोमेशन के माध्यम से प्रत्येक संपत्ति का पूरा जीवनचक्र ट्रैक किया जाएगा। पंजीकरण, लेखा-जोखा, ऑडिट और मुकदमेबाजी सभी ऑनलाइन और पारदर्शी होंगे। छह माह के भीतर सभी संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज हो जाएंगी, जिससे कोई भी संपत्ति छिपी नहीं रहेगी। यह पारदर्शिता भ्रष्टाचार को कम करेगी और वक्फ बोर्डों को एक वैज्ञानिक, उत्तरदाई और आधुनिक संस्था में परिवर्तित कर देगी। परिणामस्वरूप, संपत्तियों का उपयोग अधिक प्रभावी, सुव्यवस्थित और न्यायसंगत ढंग से सुनिश्चित होगा।

जिला कलेक्टर को संपत्ति सर्वेक्षण और विवाद समाधान की जिम्मेदारी दी गई है, जो प्रबंधन का सबसे मजबूत स्तंभ साबित होगा। अब निर्णय केवल सरकारी रिपोर्टों और निष्पक्ष जांच पर आधारित होंगे। अतिक्रमण स्वतः रोक जाएगा और संपत्तियां उनके वास्तविक लाभार्थियों तक सुरक्षित रूप से पहुंचेंगी। कलेक्टर का समयबद्ध और तथ्यपरक ट्रिब्यूनल हर निर्णय को मजबूत और भरोसेमंद बनाएगा। इसके परिणामस्वरूप, वक्फ संपत्तियां शीघ्र और प्रभावी कल्याण कार्यों में लागू होंगी। विवाद कम होंगे, संपत्तियों का विकास तेजी से होगा और गरीब, विधवा एवं वंचित वर्गों तक लाभ

वक्फ के लिए नए नियम

सुनिश्चित रूप से पहुंचेंगे। यह व्यवस्था स्थानीय प्रशासन की दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। समावेशिता और संतुलित नेतृत्व अब वक्फ बोर्ड की नई पहचान बन चुका है। बोर्ड में अब कम से कम दो मुस्लिम महिलाएं और गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे। विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों का प्रतिनिधित्व भी अनिवार्य होगा। इससे निर्णय प्रक्रिया व्यापक दृष्टिकोण वाली, संतुलित और संवेदनशील बनेगी। महिलाओं की भागीदारी प्रबंधन में संवेदनशीलता और सुझाव लाएगी, जबकि गैर-मुस्लिम सदस्य प्रशासनिक निगरानी और सहयोग सुनिश्चित करेंगे। यह संरचना वक्फ को केवल धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संपदा और सामाजिक उत्तरदायित्व का सशक्त प्रतीक बनाएगी। प्रत्येक वर्ग का सक्रिय योगदान विकास की दिशा में सुनिश्चित होगा और कल्याण कार्यों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। संपत्ति दान और वक्फ गठन के नए नियम इसे सुरक्षित, पारदर्शी और न्यायसंगत बनाते हैं। अब केवल पांच वर्ष से इस्लाम का पालन करने वाला वास्तविक और सच्चा मालिक ही संपत्ति वक्फ कर सकेगा। वक्फ बाय यूजर जैसे पुरानी और असुरक्षित प्रथाओं पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

स्वास्थ्य विषमता के विरुद्ध सबसे बड़ा अस्त्र है वैज्ञानिक चेतना

हर वर्ष 7 अप्रैल को 'विश्व स्वास्थ्य दिवस' मनाया जाता है, जो मानव सभ्यता को आईना दिखाने वाला एक वैश्विक आत्ममंथन है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य केवल अस्पतालों, दवाइयों और डॉक्टरों तक सीमित अवधारणा नहीं बल्कि एक समग्र स्थिति है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन निहित है। इस वर्ष यह दिवस स्वास्थ्य के लिए एकजुट विज्ञान के साथ खड़े रहें थीम के साथ मनाया जा रहा है, जो अत्यंत प्रासंगिक, विचारोत्तेजक और दूरदर्शी संदेश लेकर आ रहा है। विश्व की आधी से अधिक आबादी आज भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है और करोड़ों लोग ऐसे हैं, जिन्हें अपनी आय का बड़ा हिस्सा केवल इलाज पर खर्च करना पड़ता है। यह स्थिति न केवल आर्थिक असमानता को बढ़ाती है बल्कि सामाजिक न्याय की अवधारणा पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है।

कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी ने तो पूरी दुनिया के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया कि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली कितनी भी विकसित क्यों न हो, यदि उसमें समावेशिता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है तो वह संकट के समय लड़खड़ा सकती है। विकसित देशों में भी स्वास्थ्य संसाधनों की कमी ने यह सिद्ध किया कि केवल आर्थिक समृद्धि पर्याप्त नहीं बल्कि वैज्ञानिक तैयारी, स्वास्थ्य अवसरों का और जनविश्वास का समन्वय ही वास्तविक स्वास्थ्य प्रदान करता है। महामारी के दौरान वैक्सीन, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को लेकर फैली अफवाहों और गलत

कुलमिलाकर, विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें एक सामूहिक संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत चिंता नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करें।

सूचनाओं ने यह भी दिखाया कि विज्ञान के प्रति अविश्वास स्वयं एक बड़ा स्वास्थ्य संकट बन सकता है। इसलिए इस वर्ष की थीम हमें यह संदेश देती है कि विज्ञान के साथ खड़ा होना केवल एक कल्प नहीं बल्कि मानवता के अस्तित्व की आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में यह विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एक विशाल और विविधतापूर्ण जनसंख्या वाले देश के रूप में भारत के सामने स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियां बहुआयामी हैं। एक ओर संक्रामक रोगों का खतरा अभी भी बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर गैर-संचारी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां आज देश में मृत्यु के प्रमुख कारण बन चुकी हैं। बदलती जीवनशैली, असंतुलित आहार, मानसिक तनाव और शारीरिक निष्क्रियता ने इन रोगों को और अधिक बढ़ावा दिया है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि आने वाले वर्षों में इन बीमारियों का बोझ और भी अधिक बढ़ने वाला है, जिससे स्वास्थ्य प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। इसके साथ ही भारत में जनसंख्या संरचना में हो रहे परिवर्तन भी एक नई चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि के साथ अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी

बीमारियों का प्रसार बढ़ने की आशंका है। यह न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बल्कि सामाजिक और आर्थिक संरचना के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। इन परिस्थितियों में केवल पारंपरिक स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त नहीं होंगी बल्कि एक समग्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया आवश्यक होगा, जिसमें रोकथाम, जागरूकता और दीर्घकालिक देखभाल को प्राथमिकता दी जाए। स्वास्थ्य अवसरों की बात करे तो भारत में अभी भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच गहरी खाई मौजूद है। जहां शहरों में आधुनिक अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी देखी जाती है। डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की कमी इस समस्या को और जटिल बनाती है। ऐसे में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं, टेलीमैडिसिन और ई-हेल्थ प्लेटफॉर्म एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में उभर रहे हैं। यह तकनीकी दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है लेकिन इनका प्रभावी उपयोग तभी संभव है, जब डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट की पहुंच को भी समान रूप से बढ़ाया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में एक स्वास्थ्य की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह दृष्टिकोण मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक-दूसरे से जुड़ा हुआ मानता है। इसलिए स्वास्थ्य नीतियों को केवल चिकित्सा तक सीमित न रखकर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास से भी जोड़ना होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान और डेटा-आधारित नीतियों के माध्यम से ही इन जटिल चुनौतियों का समाधान संभव है। आज के समय

में एक और बड़ी चुनौती है ग्रामिक सूचनाओं का प्रसार। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार के साथ गलत जानकारी तेजी से फैलती है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसान करती है। वैज्ञानिक विरोधी अभियान, अप्रमाणित उपचार पद्धतियों का प्रचार और छद्म विज्ञान के बढ़ते प्रभाव ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक नया खतरा उत्पन्न कर दिया है। इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक तथ्यों को सरल और प्रभावी तरीके से आम जनता तक पहुंचाया जाए और लोगों में वैज्ञानिक सोच विकसित की जाए। सरकारों की भूमिका भी इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य बजट में वृद्धि, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, अनुसंधान को प्रोत्साहन और स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वभौमिकरण ऐसे कदम हैं, जो इस दिशा में निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं। भारत में आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं, जिनका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। लेकिन इन योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उनका क्रियान्वयन कितनी पारदर्शिता और प्रभावी शैली में किया जा सकेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स, जीनोमिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। रोगों की प्रारंभिक पहचान, व्यक्तिगत उपचार और दवाओं के विकास में यह तकनीकी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। हालांकि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन तकनीकों का लाभ



योगेश कुमार गोयल

समाज के हर वर्ग तक पहुंचें और यह केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित न रहे जाए। यह समझना भी आवश्यक है कि स्वास्थ्य केवल सरकारों या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं बल्कि यह एक सामूहिक दायित्व है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा और स्वस्थ जीवनशैली अपनानी होगी। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान और स्वच्छता जैसे छोटे-छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही समाज में सहयोग और संवेदनशीलता की भावना को भी बढ़ावा देना होगा ताकि कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे। विश्व स्वास्थ्य दिवस का संदेश यही है कि यदि हमें एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की कल्पना करनी है तो हमें विज्ञान के साथ खड़ा होना होगा। वैज्ञानिक सोच, वैश्विक सहयोग और मानवीय संवेदनाओं का संगम ही वह मार्ग है, जो हमें स्वास्थ्य की समानता और सार्वभौमिकता की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। यह केवल एक दिवस का संदेश नहीं बल्कि एक सतत संकल्प है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)



शिमला। लाहौल-स्पीति जिले के रोहतंग स्थित अटल सुरंग के उतरी प्रवेश द्वार पर बर्फ के बीच साहसिक गतिविधियों में भाग लेते पर्यटक।

जापोरोजे परमाणु ऊर्जा संयंत्र में स्थिति लगातार तनावपूर्ण: चेर्न्युक

मास्को। जापोरोजे परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निद-शक यूरी चेर्न्युक ने कहा है कि संयंत्र की सुविधाओं और शहर पर युद्ध के प्रभाव के कारण वहाँ की स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। संयंत्र की प्रवक्ता एवगेनिया याशिना ने शुक्रवार को बताया था कि पिछले दो हफ्तों में जापोरोजे परमाणु ऊर्जा संयंत्र और एनरगोदर के पास के क्षेत्र में यूक्रेन के सशस्त्र बलों के हमलों की तीव्रता में काफी वृद्धि हुई है। रोसाटोम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलेक्सी लिखाचेव ने रविवार को कहा कि पिछले कुछ दिनों में संयंत्र क्षेत्र पर कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन स्टेशन के अनुपंगी शहर एनरगोदर पर हमले हुए हैं।

पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण ऊर्जा संकट की है आशंका: मेलोनी

रोम। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने स्वीकार किया है कि यदि पश्चिम एशिया में स्थिति और बिगड़ती है तो देश को ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ सकता है। 'कोरिरे डेला सेरा' अखबार ने इटली के चार हवाई अड्डों-मिलान, वेनिस, ट्रेविसो और बोल्गोना में जेट ईंधन पर लागू किए गए पहले प्रतिबंध को जानकारी दी। सुमेलोनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि जब खाड़ी देशों में अस्थिरता बढ़ती है, तो इसका सीधा असर ऊर्जा की लागत, व्यवसायों, नौकरियों और अंततः परिवारों की क़य शक्ति पर पड़ता है। प्रधानमंत्री का मानना है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में फारस की खाड़ी के देश प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अगर वहाँ उत्पादन कम या बंद होता है, तो ऊर्जा की कीमतें हर किसी के लिए बढ़ जाएंगी।

अमेरिका ने अपने ही विमानों पर बमबारी की: IRGC

ट्रम्प की बेइज्जती से बचने और अपनी सेना की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा: ईरानी वायु रक्षा कमान

तेहरान/नई दिल्ली। ईरान के वायु रक्षा कमान ने कहा है कि अमेरिका की सेना ने बचाव अभियान के दौरान अपने ही विमानों पर बमबारी कर दी। ईरान के एकीकृत वायु रक्षा कमान 'खातम अल-अबिया मुख्यालय' के प्रवक्ता ने कहा कि जब ईरान के लड़ाकू विमानों ने घेराबंदी पूरी कर ली, तो ट्रम्प की बेइज्जती से बचने और अपनी सेना की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपने ही गिराए गए विमानों, साजो-सामान, कमांडरों और सैनिकों पर भारी बमबारी करने को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के कई विमानों को निशाना बनाया गया और उन्हें इस्फ़ाहन के दक्षिण में आपातकालीन लैंडिंग करने पर मजबूर होना पड़ा। इनमें दो सी-130 सैन्य परिवहन विमान और दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर शामिल थे। इस्लामिक रिवालयूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने एक बयान में अमेरिका के इस अभियान को 'बिफल' बताया गया और कहा गया कि इसके परिणाम को 'सिर्फ' बयानबाजी, मीडिया युद्ध या मनोवैज्ञानिक अभियानों से ठीक नहीं किया जा सकता। वहीं ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने तेहरान के 'शरीफ प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय' को निशाना बनाकर किए गए कथित 'बंकर-बस्टर' बम हमले को निंदा



शरीफ विश्वविद्यालय पर हमला ट्रम्प की अज्ञानता का प्रतीक: मोहम्मद रजा आरिफ बंकर-बस्टर बम हमले की निंदा की

करते हुए इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रम्प की 'बर्बता' करार दिया है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त आरिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि शरीफ विश्वविद्यालय पर बंकर-बस्टर बम हमला ट्रम्प के पागलपन और अज्ञानता का प्रतीक है। ईरानी उपराष्ट्रपति ने कहा कि वह (ट्रम्प) यह समझने में विफल रहे हैं कि ईरान का ज्ञान केंद्रों में नहीं दबा है जिसे बमों से नष्ट किया जा

सके, असली किला तो हमारे प्रोफेसरों और लोगों की इच्छाशक्ति है। आरिफ ने जोर देकर कहा कि इतिहास की कोई भी बर्बता ईरानी लोगों से विज्ञान को छीनने में कभी सक्षम नहीं हुई है।

विज्ञान हमारी आत्माओं में रचा-बसा है और यह किला कभी नहीं ढहेगा। गौरतलब है कि सोमवार तड़के हुए इस हमले पर अमेरिका ने फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। शरीफ विश्वविद्यालय की तुलना अक्सर अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) से की जाती है, क्योंकि ईरान में वैज्ञानिक अध्ययन को आगे बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े कई प्रोफेसरों की पहले ही हत्या की जा चुकी है, जिन पर देश के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े होने के आरोप थे।

जापान ईरान के साथ सीधे संपर्क का कर रहा है उपयोग: ताकाइची

टोक्यो। प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच जापान होमूज जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ईरान के साथ सीधे संचार माध्यमों का उपयोग कर रहा है। सुताकाइची ने संसद में प्रश्नों के उत्तर में कहा कि हमने आज तक विभिन्न स्तरों पर ईरान के साथ धनियत संचार बनाए रखा है। फारस की खाड़ी में जापान से जुड़े जहाजों सहित कई जहाजों के फंसे होने पर चिंता व्यक्त करते हुए, हम मांग करते हैं कि ईरानी पक्ष होमूज जलडमरूमध्य में सभी जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि इसके साथ इस सीधे माध्यम का उपयोग करते हुए, हम होमूज जलडमरूमध्य में नौवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित उपायों की तलाश जारी रखेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि होमूज जलडमरूमध्य में जापानी जहाजों सहित सभी जहाजों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जाए। उल्लेखनीय है कि अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान में हमले शुरू किए थे। ईरान, इजरायली क्षेत्र के साथ-साथ पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ जवाबी कार्रवाई कर रहा है।

युद्ध कई साल चला, तो भी नहीं होगी मिसाइलों की कमी: ईरान

सैन्य कार्रवाइयों के दौरान पूरी दुनिया के सामने कई क्षेत्रों में अपनी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन किया

तेहरान/काहिरा। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका और इजरायल के साथ सैन्य संघर्ष कई सालों तक चलता है, तब भी उसके पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं होगी। यह बात ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति पर संसदीय आयोग के सदस्य अलाएदीन बोरूजेदी ने रविवार को कही।



अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए, जिसमें तेहरान भी शामिल था

ईरान के बहरेस्तान में अमेरिका और इजरायल के हमले में 13 लोगों की मौत

तेहरान। अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के बहरेस्तान में किए गए हमलों में 13 लोगों की मौत हो गई। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी और इजरायली सेना ने बहरेस्तान क्षेत्र के कुलेह मीर शहर में दो रिहायशी इमारतों पर बमबारी की, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। गौरतलब है कि यह क्षेत्र तेहरान प्रांत का एक घनी आबादी वाला इलाका है। बहरेस्तान के गवर्नर ने बताया कि मलबे को हटाने और मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए तलाशी अभियान जारी है।

अमेरिका-इजरायल के हमले में ईरान में छह बच्चों की मौत

मास्को। ईरान के तेहरान प्रांत पर रात भर चले अमेरिकी और इजरायली हमलों में कम से कम छह बच्चों की मौत हो गई है। प्रेस टीवी ने आपातकालीन सेवाओं के हवाले से बताया है कि तेहरान के आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार चार बच्चों और दो बच्चों की मौत हुई, जिनकी उम्र 10 साल से कम थी। गौरतलब है कि अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान में कई ठिकानों पर हमले शुरू किए थे, जिसमें तेहरान भी शामिल था। इससे काफी नुकसान हुआ और आम नागरिकों की जानें गयीं। इसके जवाब में ईरान इजरायली क्षेत्र के साथ-साथ पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है।

राजनाथ ने देश के चारों कोनों में सेना के रिसर्च और रेफरल अस्पताल बनाने का सुझाव दिया

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी मेडिकल कोर के 262 वें स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत सोमवार को यहां सेना अस्पताल (रिसर्च एंड रेफरल) में नेत्र विज्ञान, कैंसर चिकित्सा तथा ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सेंटर्स की आधारशिला रखी तथा दिल्ली छावनी स्थित बेस अस्पताल में नए बुनियादी ढांचे का शिलान्यास किया।

रक्षा मंत्री ने सैन्य चिकित्सा के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर नवाचार, क्षमता निर्माण और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया।



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य नर्सिंग सेवा की नर्सों के योगदान की सराहना की

सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब सैनिकों को श्रेष्ठ चिकित्सा सहायता का विचार होता है, तो वे बिना भय के अपने मिशन पूरे करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक मानकों से नहीं आंकी जा सकती, बल्कि जनस्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण आयाम है। चिकित्सा क्षेत्र को बदलती चुनौतियों के अनुरूप स्वयं को निरंतर अद्यतन करना होगा और समय विकास की दिशा में आगे बढ़ना होगा। रक्षा मंत्री ने सैन्य नर्सिंग सेवा की नर्सों के योगदान की सराहना की।

चीन ने रूसी नागरिकों के वास्ते वीजा-मुक्त व्यवस्था को बढ़ाया

मास्को। चीन ने रूसी नागरिकों के लिए वीजा-मुक्त व्यवस्था को एक साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इजवेस्टिया अखबार ने रूसी विदेश मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से अपनी रिपोर्ट में यह खबर दी है। मंत्रालय ने अखबार को बताया कि हमारे साझेदारों ने हमें पहले ही सूचित कर दिया है कि वे रूसी नागरिकों के लिए वीजा-मुक्त व्यवस्था को एक और साल के लिए बढ़ाने को तैयार हैं। हम आपसी यात्रा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तैयार हैं।

ग्राम के विकास के लिए समर्पित

फिरोज बेग

ग्राम प्रधान पद के युवा, शिक्षित व ईमानदार प्रत्याशी

ग्राम पंचायत रेहड़

आवश्यकता है

जामिया इस्लामिया अरबिया मुबारिया स्कूल, चरशावल रोड

(English Medium - कक्षा 1 से 5 तक)

विद्यालय हेतु एक योग्य एवं अनुभवी प्रधानाचार्य (Principal) तथा प्रशिक्षित अध्यापकों (Teachers) की आवश्यकता है।

प्रधानाचार्य के लिए योग्यता:

स्नातक/स्नातकोत्तर (शिक्षा में वरीयता) B.Ed

अध्यापक के लिए योग्यता:

स्नातक/स्नातकोत्तर (संबंधित विषय में) B.Ed/BTC

आकर्षक वेतन (योग्यता एवं अनुभव के अनुसार), अनुवासित एवं शैक्षणिक वातावरण

प्रवेश संबंधित सूचना: प्रवेश प्रारंभ (Admissions Open)

मासिक शुल्क: 50 रु. मात्र, प्रवेश नि:शुल्क (Free Admission)

स्थान: चरशावल रोड: इस्कु अन्वरुद्दीन अपना Resume शीट भेजें या संपर्क करें।

M. : 9368215210

यौन समस्याएं

यौन समस्याओं के विशेषज्ञ

पुराने से पुराने यौन रोग के मरीज एक बार अवश्य मिलें

डा. सम्राट

नशामुक्ति, शराब, बीडी, सिगरेट, गुटखा तम्बाकू, प्रोक्सीवांन कैप्सूल अफीम, चरस, डोडे पोस्ट इंजेक्शन व अन्य नशा छुड़ाने का स्थायी इलाज।

नावल्टी सिनेमा चौक मुजफ्फरनगर (यू.पी.)

M-941221108

श्री कृष्णा वोकेशनल एण्ड पैरामेडिकल कॉलेज

गांधी कॉलोनी, मेन पवैण्डा रोड, निकट गऊशाला, मुजफ्फरनगर

प्रवेश सूचना-पैरामेडिकल/वोकेशनल एण्ड यूनियवर्सिटी कोर्स

10th व 12th (OPEN Board) से करें (विषय-साइंस, आर्ट, कॉमर्स etc.)

प्रवेश-10th हेतु- 8th पास/10th फेल, 12th हेतु-10th पास/12th फेल (Fresh, Part Admission & TOC Facility Available) (Exam-July व Oct 2026)

NIOS (शिक्षा मंत्रालय) कोर्स- D.N.V.S, Radiology (X-Ray Tech), CCH (एकोपेरिक), CAT (आधुनिक-पंचकर्म टैक), CHD (होम्योपैथिक), Diploma in Yoga & YTP, ECCE- (प्री-प्रार्थमिक शिक्षक हेतु), CCA (कम्प्यूटर), ET (डेलीक्टक टैक.) ETC.

Contact us for UGC Approved University Courses:- Dip. in CMS&ED, Dip. in Panchakarma Therapy, OT Tech., DMLT, BMLT, BNYS, Optometry, Ophthalmic, Dental Tech & Hygiene, Radiology & Imaging Tech, Dietician and Nutritionist, Optician Dispensing, MPH/W, MRT, Agriculture, Bachelor (All Paramedical) BBA, MBA, BSC, MSC, B.Com, M.Com, M.A. B.A. Polytechnic, ITI, Nursing Assitant Etc.

M.: 8505978850, 9634519104

ADMISSION OPEN

Mom & Me

NURTURING WITH LOVE

PLAY | NURSERY | LKG | UKG | 1st to 4th

M.: 9997023008

Branch1- New Mandi, Near Bala ji Dham Chowk

Branch2- Circular Road, Opp. Canara Bank

जो माता-पिता अपने बच्चों की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं हैं और अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर होशियार और सफल बनाना चाहते हैं तो संपर्क करें!

Unique COACHING CENTRE

ESTD. 1995

UNIQUE SUCCESS POINT

पहले देखें! फिर विश्वास करें! FREE 10 DAYS DEMO

आपकी एक मीटिंग हमारे साथ आपके बच्चों का जीवन बदल सकती है!

BOTH U.P. & C.B.S.E. BOARD STUDENTS CLASS 1 TO X

+91 7505612792 DIR- LOKESH CHAUHAN (M.Sc (Phy), B.Ed)

+91 9412507193